ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-5* August-2021
Anthology : The Research

कोविड -19 और बेरोजगारी
Covid-19 and Unemployment

Paper Submission: 03/08/2021, Date of Acceptance: 15/08/2021, Date of Publication: 25/08/2021

भुवन तिवारी
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
एम0बी0पी0जी0 कॉलेज,
हल्द्वानी, उत्तराखंड, भारत

तारा चन्द्र
शोध छात्र,
राजनीति विज्ञान विभाग,
एम0बी0पी0जी0 कॉलेज,
हल्द्वानी, उत्तराखंड, भारत
सहायक प्राध्यापक
(गेस्ट फैक्लटी)
जी0डी0सी0, थलीसैंण
(पौड़ी गढ़वाल), उत्तराखंड,
भारत

'कोविड-19' अर्थात कोरोना वायरस डीसीज - 2019। नॉवेल कोरोना वायरस का पहला मामला 2019 के अन्त में चीन के वुहान हुबेई प्रान्त में मिला था। तब इस जानलेवा वायरस से सम्पूर्ण वैश्विक समुदाय अनभिज्ञ था। जानलेवा वायरस के पूरी दुनिया में तबाही मचाने के बाद दुनिया के कई देशों ने यह आरोप लगाये है कि यह घातक वायरस प्राकृतिक नही बल्कि कृत्रिम है जिसे चीन के द्वारा वुहान के लैब में तैयार किया गया है। किन्तु चीन इस प्रकार के बयानों को झूठे आरोप कहकर सिरे से खारिज करते हुए आ रहा है। यह वायरस प्राकृतिक है या अप्राकृतिक यह स्पष्ट नहीं है। किन्तु इसके द्वारा की गई तबाही हाहाकार से पृथ्वी पर मानवजाति संकट में आ गई है।

'Covid-19' means Corona Virus DCs - 2019. The first case of the novel coronavirus was found in China's Wuhan Hubei province in late 2019. Then the entire global community was unaware of this deadly virus. After the deadly virus caused havoc all over the world, many countries of the world have alleged that this deadly virus is not natural but artificial, which has been prepared by China in the lab of Wuhan. But China is coming outrightly rejecting such statements as false allegations. It is not clear whether this virus is natural or unnatural. But due to the devastation caused by it, the human race on earth has come in danger.

मुख्य शब्दः कोरोना, लॉकडाऊन, कोविड-19, मास्क, सामाजिक दूरी, सैनेटाइजर, पी0पी0किट, आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट, थर्मल स्क्रीनिंग, वर्क फरोम होम, स्टे होम, क्वारंटाइन, होम आईसोलेट, कोवैक्सिन, कोविशील्ड, स्ट्रेन, वैरिएंट, ऑटोमोबाइल, वैकेटहॉल,
Corona, Lockdown, Covid-19, Mask, Social Distance, Sanitizer, Pp Kit, Rtpcr Test, Thermal Screening, Work From Home, Stay Home, Quarantine, Home Isolate, Covaxin, Coveshield, Strain, Variant, Automobile, Vankethall.

प्रस्तावना

निजीकरण के दौर में पहले से ही बेरोजगारी का दंश झेल रही आम जनमा के ऊपर कोविड की मार किसी अभिशाप से कम नहीं है। मार्च 2020 से जुलाई 2021 तक देश में कोरोना की दो लहरें आ चुकी है। इन दोनो लहरों ने देश को पूरी तरह से झकझोर दिया है। जहाँ मौतो का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। वहीं बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कोरोना की जानलेवा लहरों ने लाखों लोगों को मौत दे दी और करोड़ों लोगों के आजीविका के साधन समाप्त कर दिये। ऑटोमोबाइल क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, यातायात, बेंकटहॉल, छोटे-बडे व्यवसायी आदि सब कोरोना से प्रभावित हुए है।

भारत जैसे विशाल देश के विकास मार्ग में बेरोजगारी पहले से ही बाधा रही है कोरोना काल में बेरोजगारी ने सारे रिकार्ड ही तोड़ दिये। लॉकडाऊन से समाज का उच्च् वर्ग , मध्यम् वर्ग, एवं निम्न वर्ग तीनो ही बुरी तरह प्रभावित हुआ। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाल वर्ग निम्नवर्ग था जो दैनिक मजदूरी कर शाम को अपनी जरूरत की वस्तु खरीदकरजीवन निर्वाह करता था।

"कोरोना से पहले भी स्थिति भयावह थी बेराजगारी का 45 सालों का रिकार्ड टूट चुका था और अब जो नई रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 13.50 करोड़ लोग सिर्फ कोरोना के चलते बेरोजगार हो जायेंगे।" - श्री पवन खेड़ा कांग्रेस प्रवक्ता यूथ कांग्रेस के टिवटर से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई0एल0ओ0) के मुताबित कोविड-19 ने पुरूषों की तुलना में महिलाओं को नौकरी में ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पुरूषों को रोजगार मे जहाँ सुधार हुआ है वहीं महिलाओं को अब भी मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार रोजगार के मामले में पुरूषों और महिलाओ के बीच आई असमानता आने वाले समय में भी जारी रह सकती है। यद्यपि 2021 में रोजगार वृद्धि का अनुमान भी महिलाओं के रोजगार स्तर को कोविड-पूर्व स्थिति में लानेमें नाकाफी साबित होगा।

शोध पत्र की समस्या

प्रस्तुत शोध पत्र की मुख्य समस्या कोरोना और बेरोजगारी दोनों ही हैं। जहाँ कोरोना जानलेवा साबित हो रहा है, वहीं बेरोजगारी भी जानलेवा से कम न हीं है। लॉकडाऊन में क्वांरटाइन, होम आइसोलेट, वर्क फ्रॉम होम, स्टे होम जैसी स्थिति में रहकर व्यक्ति तनाव, अवसाद में पहुंच गया जो गम्भीर बीमारी के संकेत होते है। देश में प्रति वर्ष लाखों छात्र कॉलेजों से पास आऊट होते है। किन्तु रोजगार की पर्याप्त उपलब्धता न होने से लाखों की डिग्रीयाँ धरी की धरी रह जाती है। कोरोना गम्भीर समस्या बनकर उभरा है जिसकी रोकथाम के लिए विज्ञान जगत मे दिन रात रिसर्च चल रही है। कई देशों द्वारा कोरोना के रोकथाम के लिए टीके विकसित कर लिये है जिसमें भारत ने भी कोवैक्सिन और कोविशील्ड विकसित की है किन्तु मात्र टीके कोरोना रोकथाम के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि टीका लगने के बाद भी कोरोना अपनी पकड़ बना ले रहा है।

उत्तराखण्ड स्वास्थ्य निदेशालय के आंकड़ो के मुताबिक राज्य में 2020 मे महिलाओं से ज्यादा पुरूषों की मौते हुई है। 2020 में दिसम्बर तक जहाँ 36865 पुरूषों की मौत हुई वही 25354 महिलाओं की मौत हुई। 2021 के पहले चार महीनों में 13807 पुरूषोंकी मृत्यु हुई जबकि 2517 महिलाओं की

मौत हुई। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में पहाड़ से ज्यादा मैदानी क्षेत्र वाले जिलों में मौतें हुई है। अधिकांश मौतें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, और उद्यमसिंह नगर में हुई है। जबकि सबसे कम मौतें चमोली जिले में हुई हैं। पहाड़ी जनपदों में सबसें ज्यादामौतें अल्मोड़ा जिले में हुई हैं।

वाशिंगटन के अध्ययन संस्थान सेंटर फॉर ग्लोबल डेबलमेंट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि कोरोना के चलते भारत में 34 से 47 लाख लोगों की मौतें हुई हैं। यह संख्या भारत सरकार के आंकड़ों से 10 फीसदी अधिक है रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है। कि मृतकों की वास्तविक संख्या कुछ हजार या लाख नहीं बल्कि दसियों लाख है भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों पर पहले भी संदेह जताया गया है। कई शहरों में सामान्य से 10 गुना तक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए तो वहीं उत्तर प्रदेश मे गंगा नदी के किनारों कई शहरों में सैकड़ों शव बिना कोविड़ 19 प्रोटोकॉल या जाँच के दफनाए गए। 20 जुलाई 2021 को जारी रिपोर्ट जनवरी 2020 से जून 2021 के दौरान हुए मौतों पर थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर अनुमान से ज्यादा घातक सिद्ध हुई। पहली लहर दूसरी लहर के मुकाबले ज्यादा समय तक बनी रही। मार्च 2020 से फरवरी 2021 के बीच हुई मौतों का वास्तविक आंकड़ा इक्ठ्ठा ही नहीं है जबकि दूसरी लहर में लोग ऑक्सीजन, बेड, और टीकों की कमी से मारे गये।

वहीं भारत में बेरोजगारी की बात करें तो पहली लहर में अप्रैल 2020 तक बेरोजगारी दर 23.5 फीसदी तक पहुंच गई थी। शहरी बेरोजगारी दर एक वर्ष के भीतर 17.41 तक बढ़ गई। कोविड-19 की दूसरी लहर और लॉकडाऊन की वजह से शहरी क्षेत्रों में कारोबारी गतिविधियों पर गम्भीर असर पड़ा है। इससे शहरी बेरोजगारी दर 23 मई को समाप्त सप्ताह में 2.70 प्रतिशत बढ़कर 17.41 प्रतिशत हो गई। यह साल 2021 के बेरोजगारी का उच्च स्तरहै।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इण्डियन इकॉनोमिक की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थितियाँ अभी ओर गम्भीर हो सकती है। शहरी बेरोजगारी दर में 1.5 प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है। वहीं ग्रामीण बेरोजगार दर 13.52 प्रतिशत जबकि कुल बेरोजगारी दर 14.73 प्रतिशतरही है।

अध्ययन का उद्देश्य

शोध पत्र में कोरोना काल मे बढ़ती बेरोजगारी के ऊपर प्रकाश डाला गया है क्योंकि मार्च 2020 से जुलाई 2021 तक बेरोजगारी में वृद्धि का कारण कोविड-19 ही रहा है। आम जनजीवन के समक्ष यह प्रश्न खड़ा हो गया है कि किस तरह अपने रोजगार को पुनः जीवित किया जाय व्यक्ति इतना भयभीत हो गया है कि वह व्यवसाय मे पैसा लगाने से डर रहा है। इस संकट के समय में जनता की नजरें अब सरकार की राहत देने वाली नीतियों पर टिकी है कि किसी तरह महामारी को नियंत्रित करके आम जीवन को पटरी पर ला सकें।

विषय विस्तार

कोरोना ने जो दर्द लोगों को दिया है व आजीवन अविस्मरणीय है। अस्पतालों में उखड़ती सांसे, बिछड़ते अपने, अन्त समय में अपनों को न देख पाना, शमशान घाटों में दिन-रात जलती चिताएँ, गंगा किनारें बहती लाशों को कौवों -कुत्तों द्वारा नौचा जाना, चारों तरफ चीख पुकार, नम होती आँखें, यह कोई काल्पनिक नहीं वरन् कोरोना की हकीकत है। कोरोना वायरस ने दूसरी लहर में 25 साल से 60 साल तक के लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इस महामारी का अभी ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। बचाव हेतु टीके लगवाये जा रहे है फिर भी सुरक्षित नहीं है। कोरोना के बदलते स्ट्रेन व वैरिएंट से विज्ञान जगत भी हैरान है।

कोरोना के दूसरे लहर में भारत में सबसे ज्यादा सक्रंमित राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे महानगरों में इसका भयावह रूप देखने को मिला था यही वो महानगर हैं जो भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपना योगदान देते है। महामारी को रोकने नियंत्रित करने में देश दुनिया की सरकारों ने अपने देशों में कड़े से कड़े प्रतिबन्द लगा दिये जैसे सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना, सामाजिक दूरी का पालन करना, सैनेटाइज करना, पूर्ण तालाबन्दी, बेवजह घर से बाहर न निकलना आदि नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया गया। पूरी दुनिया में लॉकडाऊन से करोड़ों रोजगार समाप्त हो गये थे जिनमें कम्पनियाँ, फैक्ट्रीयाँ, होटल, मॉल, शॉप, स्कूल, जिमखाने, मन्दिर, मस्जिद, चर्च, कोचिंग संस्थान, रेलवे, परिवहन, एयरपोर्ट, बन्दरगाह, पार्क, हॉट बाजार आदि को पूर्ण रूप से बन्द कर दिया गया जिनसे लोगों का रोजगार किसी न किसी रूप से जुड़ा था।

स्थिति इतनी भयानक थी कि लोग अपनी रोजमर्रा की वस्तुओं को भी नहीं खरीद पा रहे थे। लॉकडाऊन में अधिक समय तक घर के अन्दर ही रहने से पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण होने लगा, बच्चों की शिक्षा चरमराने, मुखिया का व्यवसाय छूट जाने से, अवसाद जैसी स्थिति में आत्म हत्याएँ जैसी घटनाऐं होने लगी है। वैवाहिक रिश्ते टूटने की कगार पर आ गये। महामारी मे ये सब होने के साथ -साथ लोगो के कार्यो योजनाओं को भी बदलकर रख दिया। अर्थव्यवस्था के संचालन में बड़े उद्योगों के साथ छोटे लघु उद्योग भी जुड़े होते हैं। अर्थव्यवस्था को किसी एक देश या एक व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया जा सकता है इसके लिए एक दूसरे के बीच क्रय-विक्रय, आयात-निर्यात, आदान -प्रदान आदि का होना आवश्यक है।

कोविड़ 19 के दौर में एक ओर जहाँ पूर्ण तालाबन्दी थी। बेरोजगारी अपने चरम पर थी ऐसी स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार ने उच्च शिक्षा में प्रथम श्रेणी के पदों पर लगभग 500 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया था। बेरोजगारी को दूर करने के लिए राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। साथ ही साथ पहाड़ों से पलायन कर चुके उन लोगों को अपने जड़ जमीन को पुनः आबाद करने के लिए प्रोत्साहितकिया जा रहा है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा घोषित लॉकडाऊन में दैनिक आय-व्यय आधारित आजीविका धारकों के नियत रोजगार बाधित होने के कारण उनके सम्मुख जो आजीविका का संकट खड़ा हुआ था। वह वैश्विक स्तर पर समरूपता से देखा गया। केन्द्र सरकार के द्वारा 'गरीब कल्याण राहत पैकेज', के तहत गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ महिलाओं, बुजुर्गो और किसानों को नकद भुगतान करके आर्थिक मदद पहुंचाई गयी। मनरेगा के तहत भी लोगों कोरोजगार दिया गया।

प्रधानमंत्रो, जनधन खातों में 3 महीने तक 500 रू0 की आर्थिक मदद पहंुचाई थी जिससे गरीबों को अपना घर चलाने में कोई समस्या न आयें। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत भी मोदी जी के द्वारा 2.82 करोड़ बुजुर्गो, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए 1,405 करोड़ रूपयें की वित्तीय सहायता प्रदान की। खाद्य सुरक्षा के तहत केन्द्र सरकार के द्वारा घर बैठे बेरोजगारों के लिए एवं गरीब वर्ग के लिए सभी राशन कार्ड धारकों को 3 माह तक प्रतिमाह मिलने वाले राशन को दुगना कर दिया गया और 'फूड सिक्योरिटी एक्ट' के तहत 3 माह तक फ्री मे राशन दिया गया। कोविड-19 के समय में कोई व्यक्ति परेशान न हो इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा कुछ योजनाएँ लागू की थी -पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मनरेगा रोजगार सृजन में सहायक, उज्जवला योजना के तहत फ्री सिलेण्डर। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न राजनीतिक दलों, गैर सरकारी संगठनों के मिश्रित सहयोग से भोजन , यातायात, औषधि, ऋणमाफी, आवास किराया, विद्यालयीं फीस माफी आदि विभिन्न क्षेत्रों मे सौहार्दकारी कदम उठाये गये थे। यदपि इस कदम से अधिकांश लोग प्रभावित हुऐ हो लेकिन कुछ लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। महानगरों, शहरों एंव अन्य राज्यों से अपने गृह क्षेत्रों में वापसी करने वाले प्रवासियों को स्वदेश या प्रदेश मे राजनेताओं की पहल पर उन्हें स्वरोजगार हेतु आसान प्रक्रिया सेलाभावित्न करने का प्रयास किया गया है।

इसी तर्ज पर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 28 मई 2020 को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बेबसाइट लांच की गयी थी, जिसका उद्देश्य राज्य में लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना था। कोविड-19 के दौर में भावुक हदय वाले होटल मालिकों, फैक्ट्रीयों के स्वामियों एवं उद्योगपतियों ने अपने कामगारों को आधा वेतन दिया जबकि उनके कल कारखाने बन्द पड़े थे। इस तरह उन लोगों ने भी बेरोजगारी को बढ़ने से रोकने में सहायता की थी। कोविड-19 के कारण पीपी किट, मास्क, सैनेटाइजर, साबुन आदि से जुड़े क्षेत्र के अतिरिक्त डिजिटल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, रोजगार की वृद्धि देखी गयी कोरोना काल में मास्क व सैनेटाइजर भी लोगो के आय का साधन बना था। शुरूवाती चरण मे जो मास्क 2 से 5रू0 तक मिलता था बाद-बाद मंे उसकी कीमत 50 रू0 से 100रू0 तक बढ़ गई। हैंडसैनेटाइजरों की कीमत में उछाल देखने को मिला है। इसके अनियमित दामों की वजह से सरकार ने इसे आवश्यक वस्तु की सूची में डाल दिया है। इसके अतिरिक्त ऑनलाईन मार्केटिंग के क्षेत्र में भी वृद्धि देखी गई जैसे- ऑनलाईन शॉपिंग, होटलों रेस्तरा से ऑन लाईन खाना मँागना आदि।

कोविड-19 महामारी ने मनुष्य को न सिर्फ बेरोजगारी का दर्द दिया है, बल्कि मानसिक अवसाद, निराशा, उदासीनता, हताशा, आत्महत्या यहाँ तक कि रिश्तों में परस्पर अविश्वसनीयता जैसे दुष्परिणाम देखे गये है। एक ओर जहाँ आराम तलब उपभोक्ताओं के भोग विलास में कटौती होने के कारण बैंकट हॉल, ब्युटिपार्लर, निजी अस्पताल, होम डिलीवरी बॉय आदि जैसे तकनीकी रोजगार को ग्रहण लगा वहीं मितव्ययीतापूर्ण सादगीपरक जीवन जीने हेतु प्रेरणा की प्राप्ति हुई।

कोरोना के कारण लॉकडाऊन में घर बैठे बेरोजगार माता-पिता के बच्चों को स्कूल तक छोड़ना पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के कारण साल 2020 मे 5.3 प्रतिशत छोटे बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, कारण कोरोना था जिसने न केवल आर्थिक स्थिति को कमजोर किया बल्कि स्कूल से भी दूर कर दिया था जो परिवार स्मार्ट फोन या लैपटॉप नहीं खरीद सकते थे उनके पास पढ़ाई जारी रखने का साधन नहीं था। अन्ततः स्कूल छोड़ने को मजबूर हो गये थे। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आर्थिकी ही रोजगार का केन्द्रीय बिन्दु है किन्तु ग्रामीण परिवेश के सन्दर्भ में देखने पर ज्ञात होता है कि लोग अपने जड़ों की ओर लौटकर भूमण्डलीकरण के दौर में उपेक्षित, परम्परागत व्यवसाय की ओर स्थायी विकल्प के रूप में आगे बड़े हैं।

सादा जीवन उच्च विचार के दर्शन में भारतीय समाज अनावश्यक व्यय की प्रवृत्ति पर पुनरावलोकन करता दिखा अर्थात बेरोजगारी के मध्य मंे भी अल्पसंसाधनांे में भी जीवन जीना कोविड-19 ने हमें सिखाया है, किन्तु वर्तमान बाजारवादी अर्थव्यवस्था में जीवन जीने वाला जनमानस यदि एक महत्वपूर्ण विवाह संस्कार का उदाहरण ले तो सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर ज्ञात होगा कि यथासम्भव पहले की तरह धूमधाम से बारात न होने पर कम से कम 2 दर्जन लघु वयव्साय बेरोजगारी के आगोस में समा गये । यह कोविड़ 19 ही है जो नवम्बर 2019 से बुहान से चलकर यद्त्तन सुरसा के मुँह की तरह बढ़ते हुए अपने तीसरे दौर की दस्तक देते चला आ रहा है। किन्तु अल्पसंसाधनों के मध्य मंे अच्छा और सच्चा जीवन देने वाला कोविड-19 उन्हीं बेरोजगारों को पर्यावरण शुद्धता की पराकाष्ठा प्रदान कर गया, सिंहवलोकन करने पर अविरल वृद्ध नर-नारी यह अनुभव करते या परस्पर अनुभ साझा करते पाये गये कि वास्तव में हम रोजगार के नाम पर कितना कुछ अनावश्यक मानव मूल्यों को तिलांजलि दे चुके थे।

शोध पत्र से सम्बन्धित सूचनाऐ

गत वर्ष से फैले कोरोना वायरस का प्रकोप अभीतक बरकरार है क्योंकि देश दो लहरों से त्रस्त, तीसरे लहर के मुहाने पर बैठा है। एक शोध के मुताबिक तीसरी लहर, दूसरी लहर से 1.7 गुना अधिक घातक होगी। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाऊन लगाया गया जिसका उल्लंघन करने पर भारत सरकार ने महामारी एक्ट 1897 मंे निम्न धाराओंके तहत कार्यवाही का प्रावधान किया है।

धारा - 188, लॉकडाऊन का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत 2 माह की जेल , 200रू0 जुर्माना। धारा 269 - इसके तहत कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कृत्य करता है जिससे दूसरे व्यक्ति को जान का खतरा पैदा हो, जो दण्डनीय अपराध है। इसके तहत 6 माह का कारावास या अर्थ दण्ड दोनों। अन्य धाराऐ 271, 144, भी लागू की गई थी जिसका उल्लंघन दण्डनीय अपराध है।

उत्तराखण्ड में ही मई 2020 मे 5400 लोगों, तो जून 2021 मंे 19,872 के खिलाफ कोविड नियमों के उल्लघंन पर कार्यवाही की गई साथ ही पुलिस ने मई 2020 में 10,800 रू0 और जून 2021 में 2 करोड़ 73 लाख 2 हजार का जुर्माना वसूल किया।

भारत में कोरोना की पहली लहर में सर्वाधिक मृत्यु दर वाले राज्यों में पंजाब 2.89 प्रतिशत, गुजरात 2.71 प्रतिशत, महाराष्ट्र 2.71 प्रतिशत, दिल्ली 2.03 प्रतिशत, बंगाल 1.94 प्रतिशत, मध्य प्रदेश 1.88 प्रतिशत, तमिलनाडु 1.63 प्रतिशत थे तथा राष्ट्रीयदर 1.61 प्रतिशत थी।

कोरोना के कारण बढ़ती बेरोजगारी ने खाद्यान्न का संकट भी खड़ा कर दिया है। हंगर वॉच के सर्वे में 11 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, दिल्ली, तेलांगना, तमिलनाडु और पं0बगांल के 3,997 प्रतिभागियों में से 2,286 ग्रामीण क्षेत्रों से और 1808 शहरी क्षेत्रों से थे। इनमें 79 प्रतिशत प्रतिभागियों की मासिक आय लॉकडाऊन से पहले 7,000 रूपये से कम थी जबकि इनमें से 41 प्रतिशत लोग लॉकडाऊन से पहले प्रतिमाह 3,000 रू0 से कम कमाते थे, इनमें से 59 प्रतिशत प्रतिभागी दलित/आदिवासी, 23 प्रतिशत अन्य पिछड़ी जातियों (ओ0बी0सी) से और करीब 4 प्रतिशत विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पी0वी0टी0जी0) से थे। कोरोना से लोगों की 62 प्रतिशत आय घटी है। अनाज 53 प्रतिशत, दालें 64 प्रतिशत, सब्जियाँ 73 प्रतिशत, और मांसाहर पदार्थ 71 प्रतिशत, पोषण गुणवत्ता की मात्रा में 71 प्रतिशत की कमी आई है। 45 प्रतिशत घरों में अनाज खरीदनें के लिए पैसे तक नहीं है। इस दौरान मुफ्त राशन के रूप में सूखें राशन या नकद हस्तारंतरण तथा स्कूल और आँगनबाड़ी में भोजन के विकल्प के रूप में सरकारी मदद आधे से अधिक लोगो तक पहुंची है।

कोविड-19 संक्रमण के मामले घटने के साथ देशभर में लॉकडाऊन खत्म करने की शुरूआत हो चुकी है। सैन्टर फॉर मॉनिटरिंग इण्डियन इकॉनॉमी ने दावा किया है। कि चरणबद्ध तरीके से लॉकडाऊन हटने से असंगठित क्षेत्र में लगभग 1.7 करोड़ रोजगार वापस आ सकते है। यह आंकड़ा दूसरी लहर मंे दोनों क्षेत्र (संगठित और असंगठित) में बेरोजगार कुद 2.5 करोड़ लोगों का करीब 66 प्रतिशत होगा।

निष्कर्ष

21 वीं शताब्दी के आरम्भ होते ही देश दुनिया में कई प्रकार की आपदाएं आती रही हैं। जिसका प्रभाव लगभग उतना नहीं रहा यदपि जान माल के नुकसान की भरपाई करना सम्भव नहीं है किन्तु उसका समाधान निकालने का हर सम्भव प्रयास किया जाता रहा है। किन्तु कोरोना वायरस इस शताब्दी का शायद सबसे बड़ी आपदा है जिससे संसार की गति पर विराम लगा दिया है। क्रबस्थानों में जगह नहीं बची है अब तो बहती हवा पर भी सन्देह जतायाजा रहा है।

कोविड- 19 ने प्रत्येक देश की सरकारों के लिए - चुनौति खड़ी कर दी है एक ओर जहाँ सरकारों को अपनी जनता का स्वास्थ्य बचायें रखना है वहीं दूसरी तरफ उसके लिए रोजगार की उपलब्धता करनी है। भारत में भी केन्द्र सरकार एंव राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाओ के द्वारा गरीब एवं बेरोजगार लोगों तक हर सम्भव मदद पहुंचाने का प्रयास किया है। सड़क राजमार्ग, वायुमार्ग, जलमार्ग अवरूद्ध होने के कारण अत्यावश्यकीय सेवा यथा दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करने वाले कार्मिक गणों आदि द्वारा निकटवर्ती अपने विभागीय केन्द्रो पर रोजगारोन्मुख स्वरोजगार के कार्यक्रमों का लाभ स्थानीय बेरोजगारों को प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदान किया गया। कोरोना वायरस इन्सानी जिन्दगी के लिए खतरा तो बन गया है किन्तु इस वायरस ने मनुष्य को खुद को पहचानने एवं अपनों को जानना सिखा दिया है। इस अदृश्य जानलेवा वायरस ने मनुष्य की भाग दौड़ वाली जिन्दगी पर विराम लगा दिया है यह भी एहसास कराया है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का खामियाजा एक न एक दिन भुगताना ही पड़ेगा।

सुझाव

प्रस्तुत शोध पत्र में कोरोना और बेरोजगारी के सन्दर्भमे यह सुझाव है कि -

1. सरकार के कोविड-19 के गाइड लाइन का पालन करना और दूसरोंको भी इसके लिए जागरूक करना।
2. सरकार द्वारा टीका अभियान के सम्बन्ध में जन मुहिम चलाना।अफवाहों के प्रति ध्यान न देकर सकारात्मक दृष्टिकोण बनायंे रखना।
3. कोविड के प्रति सावधानी और सर्तकता बरतना जरूरी है।
4. कोरोना काल में आवश्यक वस्तुआंे की जमाखोरी पर सरकारद्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए।
5. सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाने वाली फैक न्यूजपर ध्यान न देना।
6. गरीब, असहाय लोगों की यथा सम्भव मदद करनी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *शेखर अरविन्द, देहरादून एस0एन0बी0*
2. *न्यूयार्क टाइम्स न्यूज सर्विस*
3. *प्रतियोगिता दर्पण जुलाई, 2020*
4. *इण्डिया टूडे*
5. *हिन्दुस्तान, 22 जुलाई 2021*
6. *दैनिक भास्कर, नई दिल्ली।*
7. *हिन्दुस्तान, 21 जुलाई 2021*
8. *हिन्दुस्तान, 17 जुलाई 2021*
9. *अमर उजाला, 11 जून 2020 कारोबार*
10. *चटर्जी पत्रलेखा, प्रवाह अमर उजाला*
11. *आसिफ सैय्यद अली वारसी, एडवोकेट इंदौर*
12. *हिन्दुस्तान 21 सितम्बर 2020*
13. *सुमसामयिक घटना चक्र -जुलाई अगस्त 2020*

इन्टरनेटः

14. *Navbhartimes.indiatimes.com*
15. *Hindi.new18.com*
16. *www.aajtak.in*
17. *financialexpress.com*
18. *Amarujala.com*